

निराश करती है जनप्रतिनिधि अपराध मामलों में देरी



ललित गर्ग

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो
यह है कि साफ-सुथरी
एवं अपराधमुक्त
राजनीति का दावा करने
वाले दल ही सर्वाधिक
अपराधी लोगों को
उम्मीदवार बना रही है।
विडंबना है कि यह
प्रवृत्ति कम होने के
बजाय हट अगले चुनाव
में और बढ़ती ही दिख
रही है। आखिर कब
तक अपराधी तत्व हमारे
भारत-विधाता बनते
रहेंगे? कब तक आम
आदमी इस त्रासदी को
जीने के लिये मजबूर
होते रहेंगे।



तर्मान और पूर्व संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों के खिलाफ लंबित पांच हजार आपराधिक मामलों के निपटारे की सुनवाई कर रही एमपी-एमएलए अदालतों में कोई उल्लेखनीय प्रगति होते हुए न दिखना न केवल निराशाजनक है बल्कि यह कानून व्यवस्था की बड़ी विसंगति है। इस सन्दर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में आग्रह किया गया कि कोर्ट इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने एवं त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश जारी करे। अपेक्षा यह की गई थी कि इन मामलों की सुनवाई त्वरित गति से होगी, लेकिन इसका उलटा हो रहा है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान लोकसभा के 543 सदस्यों में से 251 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 170 गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिनमें पांच साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है। हाल ही दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणामों में भी आपराधिक छवि के विधायकों की बड़ी संख्या चिन्ता में डालते हुए शर्मसार कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के 48 नवनिर्वाचित विधायकों में से 16 यानी 33 प्रतिशत और आम आदमी पार्टी के 22 में से 15 यानी 68 प्रतिशत नवनिर्वाचित विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, भाजपा के सात और आप के 10 विधायक गंभीर किस्म के आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय-समय पर दिए गए आदेशों और हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं, जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक बदनुमा धब्बा हैं।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि साफ-सुथरी एवं अपराधिक राजनीति का दावा करने वाले दल ही सर्वाधिक अपराधी लोगों को उम्मीदवार बना रही है। विडंबना है कि यह प्रवृत्ति कम होने के बजाय हर अगले चुनाव में और बढ़ती ही दिख रही है। आखिर कब तक अपराधी तत्व हमारे भाग्य-विधाता बनते रहेंगे? कब तक आम आदमी इस त्रासदी को जीने के लिये मजबूर होते रहेंगे। भारत के लोकतंत्र के शुद्धिकरण एवं मजबूती के लिये अपराधिक राजनेताओं एवं राजनीति के अपराधीकरण पर नियंत्रण की एक नई सुवध का इंतजार कब तक करना होगा? त्रासद एवं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पूर्व एवं वर्तमान विधायकों और सांसदों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित की गई अदालतें उनके मामलों का समय पर निपटारा करने में विफल साबित हो रही हैं। बड़ी संख्या में मामलों का लंबित रहना, जिनमें से कछु तो दशकों से लंबित हैं, यह

दर्शाता है कि सांसदों एवं विधायकों का अपने विरुद्ध मामलों की जांच या सुनवाई पर बहुत अधिक प्रभाव है औ अपने राजनीतिक वचस्प एवं प्रभाव के कारण मुकदमे के पूरा नहीं होने दिया जाता है। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय अपने इस दायित्व के निर्वहन सही तरह से नहीं कर पा रहे हैं। समय-समय पर ऐसी खबरें भी आती रही हैं कि एमपी-एमएलए अदालतों को जनप्रतिनिधियों के मामलों के निपटारे में तेजी लाने के कहा है, लेकिन इसके कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ सके। समझना कठिन है कि जिन अदालतों का गठन ही कुछ विशेष मामलों के निस्तारण के लिए हुआ है, वे उनको सुनवाई में प्राथमिकता का परिचय यहों नहीं दे रही हैं? उचित यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन अदालतों को यह स्पष्ट निर्देश दे कि वे जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई एक निश्चित समय सीमा में करें और ऐसा करने के लिए उच्च न्यायालयों को निर्देशित करें। यदि ऐसा कुछ नहीं किया जाता तो राजनीति के अपराधीकरण को रोकना बहुत कठिन होगा और आपराधिक छवि के नेताओं के मामले न्यायालयों में बढ़ते ही जायें। यह स्थिति लोकतंत्र का उपहास उड़ाने वाली ही है। यह स्थिति अधिक चिन्ताजनक एवं दुखाली है इसलिये भी है कि अब तो गंभीर आपराधिक मामलों में जेल में बंद लोगों को चुनाव प्रचार के लिए भी जमानत देने का सिलसिला कायम हो गया है। जनप्रतिनिधि भी रक्षक नहीं भक्षक हो रहे हैं। ये कानून का भक्षण करने में माहिर होते जा रहे हैं। ये कैसे जनप्रतिनिधि हैं जो पहले बोत मांगते हैं फिर जीत के बाद लोगों को लात मारते हुए उनके साथ तरह-तरह के अपराध करते हैं। लोकतंत्र के मखपष्ठ प्र

बहुत धब्बे हैं, अधेरे हैं
खुला आकाश नहीं है। मैं
हो गया। क्या यही उन श
झुल गये थे? राजनीतिक
परिवर्तन हो ताकि कोई
प्रतिनिधि न बन सके।
दिल्ली नगर निगम चुना
एडीआर और हाविली
रिपोर्ट जारी कर यह बता
विजेताओं में से बयाली
पार्षद ऐसे हैं, जिन पर
अलावा, उन्नीस पार्षद गंभीर
हैं। इससे पूर्व दिल्ली में प्र
चुनाव के नतीजों के बाद
चुने गए कम से कम आठ
मामले दर्ज पाए थे। इसमें
के विधायक थे। अब प्रश्न
विधानसभा के चुनावों में
के लिए स्वच्छ छिकि के बाब
क्यों नहीं समझी? जबकि
एवं भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति
चुनावी सुधारों पर होने वाले
अपराधीकरण एक अह
अपराधीकरण-ह्याअपराधित
लेनाह्न-हमारी निर्वाचन व
गया है। मौजूदा लोकसभा
सदस्यों पर गंभीर आपराधि

लोकसभा में यह आँकड़ा तुलनात्मक रूप से कम था। राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र का एक स्याह पक्ष है, जिसके महेनजर सर्वोच्च न्यायालय और नियन्त्रन आयोग ने कई कदम उठाए हैं, किंतु इस संदर्भ में किये गए सभी नीतिगत प्रयास समस्या को पूर्णतः नियन्त्रित करने में असफल रहे हैं। हालांकि एक अच्छी पहल यह हुई है कि अब हाईकोर्ट की इजाजत के बिना सरकार किसी भी सांसद एवं विधायक के खिलाफ दर्ज मामलों वापस नहीं ले सकती है। राजनीति के अपराधीकरण के कारण चुनावी प्रक्रिया में काले धन का प्रयोग काफी अधिक बढ़ जाता है। इसका देश की न्यायिक प्रक्रिया पर भी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और अपराधियों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया धीमी हो जाती है। राजनीति में प्रवेश करने वाले अपराधी सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और नौकरशाही, कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका सहित अन्य संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। यह स्थिति समाज में हिंसा, अश्वाचार, उत्पीड़न की संस्कृति को प्रोत्साहित करती है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिये एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करती है। वैसे तो भारत का लोकतंत्र बड़े-बड़े बाहुबली एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के नेताओं के शर्मनाक कृत्यों का गवाह रहा है, बार-बार शर्मसार हुआ है। यही कारण है कि राजनीति का चरित्र गिर गया और साख घटती जा रही है।

इन वर्षों में जितने भी चुनाव हुए हैं वे चुनाव अर्हता, योग्यता एवं गुणवत्ता के आधार पर न होकर, व्यक्ति, दल या पार्टी के धनबल, बाहुबल एवं जनबल के आधार पर होते रहे हैं, जिनको आपाधिक छवि बाले राजनेता बल देते रहे हैं। आप ने भ्रष्टाचार एवं अपराधों पर नियंत्रण की बात करते हुए राजनीति का बिगुल बजाया। लेकिन यह दल तो जल्दी ही अपराधी तत्वों से घिर गया। नेताओं की चादर इतनी मैली है कि लोगों ने उसका रंग ही काला मान लिया है। अगर कहीं कोई एक प्रतिशत ईमानदारी दिखती है तो आश्चर्य होता है कि यह कौन है? पर हल्दी की एक गांठ लेकर थोक व्यापर नहीं किया जा सकता है। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ा संकट है। आदर्श लोकतंत्र एवं समाज व्यवस्था का निर्मित करने की जिम्मेदारी इन्हीं नेताओं पर है, जिनका चरित्र एवं साख मजबूत होना जरूरी है। दुःखद स्थिति है कि भारत अपनी आजादी के अमृत काल तक पहुंचते हुए भी स्वयं को ईमानदार नहीं बना पाया, चरित्र सम्पन्न राष्ट्र नहीं बन पाया।

(लेखक, पत्रकार एवं संस्थभकर)
 (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

संपादकीय

महाजाम की जटिल व्यवस्था

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालू विविध स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। 144 साल बाद पड़ रहे इस महाकुंभ में आने के रास्तों में महाजाम लग गया है। तीन सौ किमी लंबे जाम को दुनिया का सबसे बड़ा जाम बताया जा रहा है। यह विशेष पर्व ज्यो-ज्यों अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं में इसका आकर्षण बढ़ता जा रहा है। वाराणसी से प्रयागराज के मार्ग पर दस किमी लंबा जाम है। रीवा-चित्रकूट से आने वाले मार्ग पर तकरीबन सत्रह किमी ते भद्राही से प्रयागराज पहुंचने वाले रास्ते पर पंद्रह किमी, और मिजापुर से आने वाले मार्ग पर बारह किमी का महाजाम लगा है। जिला व पुलिस



के जाम से निकलने में दस दिन लग गए थे। मगर यह न तो प्राकृतिक आपादा है, न ही अचानक लगा जाम है। सरकारी दावों और व्यवस्था को लेकर तमाम प्रचार के खोखलेपन का उपहास बन रहा है। भगदड़, और बार-बार आग लगने के पीछे लापरवाही छिपी नहीं है। लखनऊ, सुलतानपुर, रायबरेली, गोरखपुर, आजमगढ़ से अयोध्या की तरफ जाने वाली सड़कों पर भी यातायात बुरी तरह प्रभावित है। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को आवागमन के लिए बंद करने के आदेश को अफरातफरी के बाद इसे अफवाह ठहरा कर लीपापेती की गई। जाहिर है, इससे यात्रियों को भारी असुविधा होती है। स्थानीय नागरिकों को हो रही दिक्कतों पर बात नहीं हो रही है जबकि उनके दिनचर्या भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है, उन्हें घरबंदी में जीना पड़ रहा है। शहर और सड़कों की क्षमता का अनुमान लगाए बगैर भव्य आयोजन और करोड़ों की धन राशि उड़ाने का उद्देश्यहीन योजना की जितनी निंदा की जाए कम है। श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कतों को बरगलाने और छश्च प्रचार से महाकुर्भ के साथ महाजाम के संगम को झुटलाने से हकीकत को बदला नहीं जा सकता।

अ मेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी भ्रष्ट आचरण कानून पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। ट्रंप के इस आदेश के बाद विदेश में व्यापार या ठेका हासिल करने के लिए अब अमेरिकी कंपनियाँ द्वारा रिश्वत देना अपराध नहीं होगा। अभी तक अमेरिकी कानून के अनुसार यह एक बड़ा अपराध था, जिसके कारण अमेरिकी सरकार अथवा अमेरिकी की कंपनियाँ जो सारी दुनिया के देशों में जो व्यापार करती थीं, इस कानून से यह संदेश जाता था, अमेरिकी की कंपनियाँ अन्य देशों में रिश्वत नहीं देती हैं। जिसके कारण अमेरिका की सरकार और अमेरिकी कंपनियों की साख फूरी दुनिया के देशों में बनी हुई थी। लुके-छुपे तौर पर यदि कोई कंपनी या व्यक्ति इस तरीके की कोशिश करता था, ऐसी स्थिति में अमेरिकी कानून के अनुसार उसे आर्थिक तथा आपराधिक मामलों में सजा से दंडित किया जाता था। ट्रंप ने जो निर्णय अभी लिया है, उससे सारी दुनिया के देशों में यह संदेश गया है। अमेरिका की कंपनियाँ अपने लाभ के लिए दुनिया के किसी भी देश के राजनेता, अधिकारियों या कारोबारियों को रिश्वत देकर ठेका हासिल कर सकती हैं। रिश्वत देकर सामान लेकर देकर देने की विधि अब अमेरिका की कंपनियों के लिए अनुमति दी गयी है।



ट्रंप ने सारी दुनिया में गिराई अमेरिका की साख

को इस है। किसी साधारण या दारेरे ने अमेरिका की निगाह समय पर भारतीय अडान और साधारण अपराधिक विकास का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर भी राजनायिक और कूटनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के पहले भारत सरकार ने जिसका तरह से आयात-निर्यात व्यापार में अमेरिका के पक्ष में शुल्क को घटाया है, वह सब अडानी समूह की राहत से जोड़कर देखा जा रहा है। ट्रंप और एलन मस्क की जोड़ी की राजनेता के स्थान पर एक कारोबारी के रूप में पहचान है। दोनों ही अपने निजी कारोबार एवं फायदे को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सरकार के निर्णय कर रहे हैं। गौतम अडानी और भारतीय कारोबार पर एलन मस्क की भी नजर है। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने में अपने चर्चेश्वर बनाने के साथ में उत्तरा

नक्सलबाद : निर्णयिक बुडाई में आगे बढ़स्था देश

बनी हुई है। उधर, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी दो टूक कह दिया है कि या तो नक्सली समाज से ज़ुड़ जाए या खात्मे के लिए तैयार रहें। नक्सली हिंसा लंबे समय से देश के अनेक प्रांतों में आंतरिक मुसीबत बनी हुई है। नई रणनीति के अंतर्गत अब सरकार की कोशिश है कि सीआरपीएफ की तैनाती उन सब अज्ञात क्षेत्रों में कर दी जाए, जहां नक्सली अभी भी टिकाना बनाए हुए हैं। इस नाते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में सबसे अधिक नक्सल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में 4000 से अधिक सैन्यबल तैनात करने जा रहा है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च 2026 तक इस क्षेत्र के पूरी तरह नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाए। इतने बड़ी संख्या में सैन्यबलों को अज्ञात क्षेत्र में पहुंच कर मतलब है कि अब इस उग्रवाद से अतिम लड़ाई होने वाली है। जिस तरह से नरेन्द्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अतंक और अलगाववाद खत्म करने की निर्णायक लड़ाई लड़ी थी, वैसी ही स्थिति अब छत्तीसगढ़ में अनुभव होने लगी है। इसमें कोई दो राह नहीं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली तंत्र कमज़ोर हुआ है, लेकिन उसकी शक्ति अभी शेष है। अब तक पुलिस व गुप्तचर एजेंसियां इनका सुराग लगाने में नाकाम होती रही थीं, लेकिन नक्सलियों पर शिकंजा कसने के बाद से इनको भी सूचनाएं मिलने लगी हैं। इसी की नतीजा है कि सैन्यबल इन्हें निशाना बनाने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर नक्सली आदिवासी हैं। इनका कायेक्षेत्र वह आदिवासी बहुल इलाका है, जिससे ये खुद आकर नक्सली बने हैं इसलिए इनका सुराग सुरक्षाबलों को लगा पान

मुष्किल होता है, लेकिन ये इसी आदिवासी तंत्र से बने मुख्यरियों से सूचनाएं असारी से हासिल कर लेते हैं। नक्सली समस्या से निपटने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दावा कर रही हैं कि विकास इस समस्या का निदान है। यदि छत्तीसगढ़ सरकार के विकास संबंधी विज्ञापनों में दिए जा रहे आंकड़ों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ की तस्वीर विकास के मानदण्डों को छूटी दिख रही है, लेकिन इस अनुपात में यह दावा बेमानी है कि समस्या पर अंकुश विकास की धारा से लग रहा है? क्योंकि इसी दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं को नक्सली बनाए जाने के प्रभाण भी मिले हैं। बावजूद कांग्रेस के इन्हीं नक्सली क्षेत्रों से ज्यादा विधायक जीतकर आते रहे हैं। हालांकि नक्सलियों ने कांग्रेस पर 2013 में बड़ा हमला बोलकर लगभग उसका सफाया कर दिया था। कांग्रेस नेता महेन्द्र कर्मा ने नक्सलियों के विरुद्ध 'सलवा जुट्टू' को 2005 में खड़ा किया था। सबसे पहले बीजापुर जिले के ही कुरुं विकासखण्ड के अदिवासी ग्राम अंबेली के लोग नक्सलियों के खिलाफ खड़े होने लगे थे। नीतीजतन नक्सलियों की महेन्द्र कर्मा से ठन गई। इस हमले में कर्मा के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल और हारिप्रसाद समेत एक दर्जन नेता मारे गए थे, लेकिन कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव में अपनी खोई शक्ति फिर से हासिल कर ली थी, बावजूद नक्सलियों पर पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपदस्थ कर भाजपा अब फिर सत्ता में है। उसके बाद से ही नक्सलियों के सफाए का सिलसिला चल रहा है।



दरअसल, देश में तथाकथित शहरी बुद्धिजीवियों का एक तबका ऐसा भी रहा है, जो माओवादी हिंसा को सही ठहराकर सर्वधानिक लोकतंत्र को मुखर चुनौती देकर नक्सलियों का हिमायती बना हुआ था। यह न केवल उनको वैचारिक खुराक देकर उन्हें उक्साने का काम करता था, बल्कि उनके लिए धन और हाथियार जुटाने के माध्यम भी खोलता था। बावजूद इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि जब ये राष्ट्रधाती बुद्धिजीवी पुष्टा सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किए गए तो बौद्धिकों और वकीलों के एक गुट ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को भी प्रभाव में लेने की कोशिश की। माओवादियों के खिलाफ जाता है, उसकी बोलती बंद कर दी जाती है, लेकिन अब इस चरमपंथ पर पूर्ण अंकश लगाता दिखाई दे रहा है।

स्वामी, प्रकाशक और मुद्रक डा० सरवर जमाल ने आर० डी० प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा० लि० प्लाट नं० 16-17 पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रीयल एरिया, रोड नं० झ० 09 पटना झ० 800013 से छपवाकर कार्यालय 203 बी, ब्लाक रंजीत रेसिडेंसीज, साकेतपुरी, मछली गली, राजा बाजार पटना- 800014 से प्रकाशित किया। सम्पादक: श्रीमती शबाना प्रवीन पी० आर० बी० एकट के तहत खबरों की जिम्मेवारे मैनेजिंग एडिटर: डा० राजीव कुमार, स्थानीय सम्पादक: डा० नृतन कुमारी, उप सम्पादक: तबस्यम नवाज PRGI NO:- BIHHIN/2023/86924 E-mail- Newsindoqulf730@gmail.com, Mob-9472871824/8544031786 समस्त विवादों का निवारण पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे।



इमरान हाशमी को अपनी असफल फिल्मों पर नहीं है कोई पछतावा

इमरान हाशमी बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है। उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों की हैं। उनके फिल्मों की अपनी एक अलग शैली रही है और उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है। इस इंडस्ट्री में, जहाँ कई सितार एक या दो फिल्मों के बाद गायब हो जाते थे, इमरान पिछले दो दशकों से इस इंडस्ट्री में सक्रिय है। इस दौरान उन्हें कई बदलाव और उत्तर-चढ़ाव देखे हैं। इस बीत उनकी कई फिल्में असफल भी हुईं। हालांकि, अभिनेता इन सभी चीजों को लेकर कोई पछतावा नहीं करता।

इमरान हाशमी लगातार अपनी फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं। इस दौरान उनकी कई फिल्मों को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। वहीं, कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। इसे लेकर उन्होंने हाल में ही एक इंटरव्यू में बता कि उन्हें कई बार किया गया है कि उन्हें पीछे मुड़कर देखने और पछतावा करने की कोई जरूरत नहीं है। वह अपनी असफल फिल्मों को गती नहीं मानते। उन्होंने कह कि हर फिल्म की अपनी एक अलग यात्रा होती है, ऐसे में वह उन्हें गती का नाम नहीं देता।

अभिनेता ने अपनी बात को विस्तार से कहते हुए बताया कि वह किंतु चीज़ को पछतावा के नजर से नहीं देखते। उन्होंने अगे कहा कि उनकी कुछ फिल्में अपने समय से आगे थीं। इस वजह से जब वो रिलीज हुई, तो लोगों के द्वारा अच्छे तरह से स्वीकार नहीं की गई। इस पर दावा करते हुए उन्होंने कहा कि वह आगे बस ऐसी फिल्मों के बारे में ही किया गया है। उन्होंने अगे कहा कि एक अभिनेता के तौर पर, उन्हें ये करना था, इसलिए उन्होंने किया, क्योंकि इन फिल्मों की स्क्रिप्ट उन्हें काफ़ी पसंद आई थी। अभिनेता ने कहा कि वह अगे बस ऐसी फिल्मों करते रहना चाहते हैं, जो उन्हें पसंद आती हैं। वह खुद को सिनेमा के प्रति जुनूनी बताते हुए कहते हैं कि वह बस दर्शकों का मनोरंजन करते रहना चाहते हैं। बात करें इमरान के वर्क फँट की तो वह इन दिनों अपनी बैब सीरीज शो टाइम को लेकर चर्चा में है। शो टाइम के सभी एपिसोड 12 जुलाई से डिजी+ हॉटस्टार पर रिलीज हुए हैं। इस सीरीज को सुसिद्ध रूप द्वारा बनाया गया है। मिहिं देसाई और अभिनेता कुमार ने इसे निर्देशित किया है। इसमें इमरान हाशमी, महिमा मकवाना, मौनी रौय, राजनव खड़ेलाल, अंजु सरन, विशाल विश्वास, नीरज मधव और विजय राज प्रमुख भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं।



खुद को बुनौती देते रहना है बेहद जरूरी

सदीप रेडी वाग की फिल्म 'एनिमल' में राजबीर कपूर के साथ भूमिका अदा करने के बाद अभिनेता तुमि दिमारी के प्रशंसकों ने उन्हें

नेशनल क्रश घोषित कर दिया था। इस फिल्म से उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली।

इससे पहले तुमि 'लैला मजनू', 'बुलबुल', 'कला' जैसी फिल्मों में काम कर चुके हैं। अब अभिनेता ने कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा है। उनकी फिल्म 'बैड न्यूज़' 15 जुलाई को सिनेमारों में दस्तक देगी। यह तुमि की पहली कॉमेडी फिल्म होगी।

अभिनेता की फिल्म 'बैड न्यूज़' को रिलीज होने में बहु कुछ दिन ही बचे हैं। इस फिल्म में उनके साथ विक्की कौशल और एमी विर्कन भी नजर आएंगे।

विद्या बालन के साथ 'भूल भुजैया 3' में नजर आएंगी। डिमारी के पास 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो', और शाजिया इकबाल की 'धड़क 2' भी है।



कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी की अफवाहों पर बोले विवक्षी कौशल

बॉलीवुड एक्टर विवक्षी कौशल ने बाइफ़ कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर उड़ रही अफवाहों पर अपना एपेक्षण अदा करने की इच्छा जाहिर की। बैड न्यूज़ की टीम का जात्याया आधार इसी बातचीत के दौरान 'एनिमल' अभिनेता ने निर्देशक आनंद तिवारी का ध्यान दिया। उन्होंने एक अनुबंध था। उन्होंने एक्षण, ड्रामा, कॉमेडी और रह तरह की भूमिकाएं अदा करने की इच्छा जाहिर की। बैड न्यूज़ की टीम का जात्याया आधार इसी बातचीत के दौरान 'एनिमल'

अभिनेता ने निर्देशक आनंद तिवारी का

ध्यान दिया। उन्होंने निर्देशक को फिल्म

में उन पर भरोसा करने के लिए आधार

जात्याया, वर्तोंकि किया ने उन्हें उस स्तर

पर कॉमेडी करते नहीं देखा है। तुमि ने

कहा, 'मेरे लिए यह बहुत शुश्रूषा थी।

कटरीना का लंदन से एक वीडियो

वायरल हुआ था जिसमें उनके पति

विवक्षी उनका हाथ पकड़कर बोक़

करते नजर आ रहे हैं।

विवक्षी के बाद वह कार्तिक आर्यन और

तुमि रेडी के बारे में बोले।

विवक्षी ने कहा कि वह उनके लिए

अच्छा था। विवक्षी ने उनके लिए

अच्छी चीज़ दी। विवक्षी

दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों की सूची जारी, भारत में बढ़ा भ्रष्टाचार का स्तर

पाकिस्तान की रैंक 135वीं तो श्रीलंका 121वें स्थान पर

नड़ दिल्ली (एजसी)। ट्रासपरसो इटरनेशनल ने 2024 का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (सीपीआई) जारी किया है, जिसमें दुनिया भर के 180 देशों और क्षेत्रों को भ्रष्टाचार के स्तर पर रैंक दी गई है। यह रिपोर्ट देशों को 0 से लेकर 100 अंक के बीच रैंक देती है। 0 अंक वाले देश सबसे भ्रष्ट माने जाते हैं, जबकि 100 अंक वाले देश को परी तरह पारदर्शी माना जाता है। 2024 में भारत की रैंकिंग 96वें स्थान पर थी, जो कि 2023 की तुलना में तीन स्थान नीचे है। भारत को इस साल 100 में से 38 अंक मिले हैं, जबकि 2023 में यह आंकड़ा 39 था। 2022 में भारत को 40 अंक मिले थे, जिसका मतलब है कि भारत में पिछले कुछ सालों में भ्रष्टाचार के स्तर में मामूली बढ़ि हुई है। 2024 की इस रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन कमज़ार रहा है, इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार की समस्या देश में अभी भी गंभीर है।

निराशाजनक है।
कि बोहट उत्तरात् ॥

करारों लागा पर पड़ रहा है, क्योंकि भूष्णाचार मानव अधिकारों को कमज़ोर कर रहा है और विकास को प्रभावित कर रहा है।

सिर्पें में पाक और अद्यम बिंदु पर ध्यान दिया

A hand holds a magnifying glass over a newspaper clipping. The word "CORRUPTION" is printed in large, bold, black capital letters on the paper. The background consists of other blurred newspaper clippings.

सीरिया शामिल हैं, जिनकी रैंकिंग सबसे नीचे है। भारत की रैंकिंग में पिरावट यह दर्शाती है कि देश में भ्रष्टाचार पर कालू पाने के लिए अभी और प्रयत्न करने की जरूरत है। सरकारी नीतियों में पारदर्शिता जवाबदेही और कड़ी निगरानी करना जरूरी है ताकि लोगों का विश्वास बढ़े और भ्रष्टाचार की समस्या समाप्त किया जा सके।

**मैं उन्हें मारकर डाँन बनना चाहता हूँ
योगी को मारने की धमकी देने वाले
युवक का बयान**

मुरैना (ईंग्लॅस)। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव के 20 वर्षीय युवक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी है। घटना तब सामने आई जब युवक ने सोशल मीडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के विजिलेंस विभाग का फोन नंबर पाकर कॉल कर दिया। युवक ने फोन पर अधिकारियों से कहा कि वहाँ सीएम योगी को मारना चाहता है, ताकि वह डॉन बन सके। युवक ने फोन पर यूपी प्रशासन के अधिकारियों से कहा कि मेरी योगी आदित्यनाथ से बात करवा दीजिए। जब अधिकारियों ने पूछा कि वह ऐसा क्यों करना चाहता है, तब युवक ने जवाब दिया, मैं उन्हें मारकर डॉन बनाना चाहता हूँ। धमकी की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की ओर एसटीएफ की दो टीमों को मुरैना भेजा। मंगलवार देर शाम जब टीम युवक के गांव पहुँची, तब उसके घर पर ताला लगा मिला। करोब 10 घंटे की तलाश के बाद युवक को पकड़ गया। युवक ने बताया कि यह सब सिर्फ मजाक में किया था। युवक ने बताया कि वह अक्सर फोन पर धमकियां देता है और कुछ ग्रामीणों ने कहा कि वह मानसिक रूप से अस्वरथ है। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी खुद ही थाने पहुँच गया और मुरैना पुलिस को परे मामले की जानकारी दी। थाने के टॉआई ने यूपी एसटीएफ के अधिकारियों को सूचित किया कि जिस युवक की तलाश थी, वह अब थाने में मौजूद है। इस घटना ने स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि कुछ ग्रामीणों ने बताया कि युवक अक्सर इस्तरह फोन कॉल करता है।

आंध्र प्रदेश में महिलाओं के लिए वर्क फॉम होम का नियम लागू करेगी नायडू सरकार

अमरावती (एजेंसी)। देश में सासाह में 90 घटे काम के बहस के बीच आंध्र प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए वर्क फॉम होम का नियम लागू करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इसकी घोषणा 11 फरवरी को पास्ट में की। हालांकि सीएम नायडू ने योजना को कैसे लागू किया जाएगा, इसके लिए कोई प्लान नहीं बताया है। सीएम नायडू ने अपनी पोस्ट में सबसे पहले मैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और युवतियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस की बधाई देता हूं। आज हम लोग उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं। हमारी सरकार महिलाओं को इन क्षेत्रों में समान मौके सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लिखा कि कोविड 19 महामारी के दौरान काम करने के तरीकों में बड़ा बदलाव आया है। तकनीकी के कारण वर्क फॉम होम करना आसान हो गया है।

सिमोट वर्क, कोवर्किंग स्पेस (सीडब्ल्यूएस) और नेब्रहुड वर्कस्पेस (एनडब्ल्यूएस) जैसी व्यवस्थाएं बिजनेस और काम करने वाले लोगों को अधिक बेहतर साथित होगा। साथ ही इससे काम की उत्पादकता भी बढ़ेगी। सीएम ने कहा कि इन पहल की वजह से वर्क और लाइफ को बैलेंस करने में मदद मिलेगी। इस मीनिंग फूल बनाने के लिए राज्य सरकार योजना पर काम कर रही है। आंध्र प्रदेश आईटी और जीसीसी नीति 4.0 इस दिशा में गेम-चैंजिंग कदम है। हमारी सरकार हर शहर, कस्बे और मंडल में आईटी ऑफिस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। साथ ही आईटी और जीसीसी कंपनियों का समर्थन कर भी कर रहे हैं, ताकि रोजगार उत्पन्न हो सके।

लालू के जंगलराज पर नीतीश का तंज... 2005 से पहले कौन लड़का-लड़की आराम से रात 11 बजे तक बाहर घूमता था

- दो बार राजद के साथ जाकर हम बहुत बड़ी गलती किया



चार साल बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत ने की कांग्रेस में घर वापसी

A photograph showing a press conference. Five men are seated behind a long table covered with a white cloth. From left to right: a woman in a blue and white sari; a man in a dark suit and patterned shirt; a man in a white shirt and orange-and-white striped sash; a man in a white shirt and orange-and-white striped sash; and an older man in a dark suit and glasses. Each man has a microphone in front of him. The background consists of a wall with several panels, each featuring the 'WEST BENGAL CONGRESS' logo, which includes a green and yellow hand icon and the text 'পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কঢ়াই কমিটি' in Bengali. The overall setting is a formal press briefing.

जॉइन करने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। अधिजीत पेशे से एक इंजीनियर हैं। राजनीति में आने से पहले उन्होंने बड़ी कॉर्पोरेट फर्मों में काम किया। प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के बाद अधिजीत 2012 के उपचुनाव में बंगलाके जंगीपुर से सांसद बने थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की लहर के बाद भी उन्हें जीत मिली थी। मगर वह 2019 के चुनाव में तुरंगमूल कांग्रेस के खलीलुर हरमान से हार गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का एक बड़ा मोड़ था। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तब उन्होंने बीजेपी को रोकने का त्रेय ममता बनर्जी को देकर कांग्रेस पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। टीएमसी में भी अधिजीत सांगठन या समरकोइंड बड़ी भूमिका में दिखाई नहीं दिए। मुख्य अपनी विवादित बयानों को लेकर सुविधियों में रहे उन्होंने 2012 में निर्भया कांड के बाद देश भर में रहे प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को डैंटेड एंड पेंस कहकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। हालांकि आलोचना के बाद उन्होंने सार्वजनिक से माफी भी मार्गी थी।

भारतीय सैनिकों के कथित अपमान पर राहुल गांधी तलब, अगली सुनवाई 24 मार्च को

बीच हुई झड़प का जिक्र किया। उहोने दावा किया कि राहुल ने कहा, “लोग भारत जोड़े यात्रा के बारे में बहुत कुछ पछ्यें, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी नहीं पूछेंगे।” विदित हो कि नौ दिसंबर को सीमा पर चीन और भारत की सेनाओं के बीच हुए विवाद के बाद 12 दिसंबर को भारतीय सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा पर अतिक्रमण कर रही था, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और इससे चीनी सेना वापस अपने इलाके में चली गई।

इसमें यह भी कहा गया था कि इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आईं। परिवाद में आरोप लगाते हुए कहा गया कि राहुल गांधी के द्वारे बयान से परिवादी को आघात पहुंचा है और लोग वादी के ऊपर भारतीय सेना को लेकर कटाक्ष करते हैं। अधिवक्ता ने कहा मामले में अदालत ने गांधी को तलब किया है और अगली तारीख 24 मार्च तय की है।

**दिल्ली का सीएम तलाशने भाजपा में मंथन, नड्डा और शाह ने 1 घंटे
लगाया दिमाग रिजल्ट शन्य**

नई दिली (ईएमएस)। दिली की जनता ने भाजपा के हाथ में सत्ता की चाबी सौंपी है। इसका मुखिया कौन होगा ये भाजपा को तय करना है। करीब 4 दिनों से इसी पर मंथन हो रहा है लेकिन सीएम कौन होगा इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। बीती रात भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बीच करीब एक घंटे विचार विमर्श हुआ लेकिन रिजल्ट शून्य ही रहा। हालांकि ये बात अलग है कि अंदर ही अंदर पार्टी ने सीएम का नाम तय कर लिया हो। सूत्रों की मानें तो अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की इस बैठक में मुख्यमंत्री के नामों पर चर्चा हुई है। इस दौरान दोनों के बीच दिली में सरकार गठन और मुख्यमंत्री के संभावित नामों पर चर्चा हुई। ऐटिंग में यह बात तय हुई कि दिली सरकार के गठन पर फैसला 16 फरवरी के बाद होगा। हालांकि, भाजपा के विधायक दलों की बैठक भी 16 फरवरी के बाद ही होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीएम कौन होगा, इस पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। जिस दिन विधायक दलों की बैठक होगी, उसमें ही सदन का नेता चुना जाएगा। वही दिली का नया मुख्यमंत्री होगा। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा राय और मोहन सिंह बिष समै कर्ह नाम हैं। बहरहाल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अभी फांस और अमेरिका की यात्रा पर हैं। वहां से लौटने के बाद भाजपा के विधायक दल की बैठक होने की संभावना है।

पीएम मोदी ट्रंप को सौंपेंगे लॉरेंस के भाई समेत इन 12 गैंगस्टरों की कंडली

नई दिल्ली। अमेरिका में छिपे गैंगस्टरों की शामत आने वाली है, जो अमेरिका में बैटकर भारत में कांड करते हैं। मोदी सरकार ने उनकी कुँडली तैयार कर ली है। एकशन का पूरा लान भी बन गया है। पीएम मोदी अमेरिका पहुंचेंगे तो गैंगस्टरों का काला चिन्ह भी पहुंच जाएगा। गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका में बैठे 12 गैंगस्टरों की लिस्ट और कुँडली तैयार कर ली है। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी जब अमेरिका में रहेंगे तो ट्रॉप प्रशासन से यह लिस्ट शेयर की जा सकती है। अमेरिका को उन गैंगस्टरों की कुँडली से वाकिफ कराने का मकसद उन सभी पर एकशन है सूत्रों की मानें तो सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि इससे सफलता मिलेगी। उन अपराधियों को भारत लाने का रास्ता भी साफ होगा। अब सवाल है कि आखिर इसमें किन-किन गैंगस्टरों के नाम हैं। भारत सरकार का यह कदम ऐसे वर्त में आया है, पिछले साल दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ था। पिछले साल भारत-अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ था। उसमें दोनों देश में जो अपराधी छिपे हैं, उस पर शिकंजा कराने के लिए सहयोग की बात थी। पिछले 8 महीने से भारत और अमेरिका के सीनियर अधिकारियों के बीच इस मुद्दे पर कई अहम बैठक हो चुकी हैं। इस सधि के तहत भारत ने भी अमेरिका को इसी तरीके की जानकारी महेया करवाई है। बीते दिनों एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिंहदीकी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले के मास्टरमाइंड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को पिछले साल नवबर में अमेरिका में गिरपतार किया गया था। इम्प्रेशन अधिकारियों ने उसे फर्जी दस्तावेजों के साथ यात्रा करते हुए पाया था। वह तब से अमेरिका की जेल में है। पिछले महीने मुंबई की एक विशेष अदालत ने बाबा सिंहदीकी की हत्या के मामले में अनमोल और दो अन्य वांछित आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था।

लंदन, बैंकॉक जाने से महंगा हुआ महाकुंभ ज

नईदिल्ली (एजेंसी)। महाकुंभ में बढ़ती भीड़ और लोगों की जरूरत के चलते कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। खासतौर से एयरलाइंस कंपनियां कछु ज्यादा ही इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। यही वजह है कि लंदन, बैंकॉक जाने से भी ज्यादा महंगा महाकुंभ जाना हो गया है। मौजूदा समय में दिल्ली से प्रयागराज के लिए हवाई किराया 80,000 रुपये तक पहुंच चुका है, जबकि लंदन की एकतरफा टिकट मात्र 31000 रुपये में मिल रही है। सामान्य दिनों में दिल्ली से प्रयागराज का हवाई किराया केवल 3,000 से 5,000 रुपये की बीच होता है। दिल्ली ही नहीं मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे अन्य प्रमुख शहरों से भी प्रयागराज जाने वाली उड़ानों के किराए में भारी उछाल देखा गया है। इन शहरों से प्रयागराज के लिए टिकट की कीमतें मुख्य स्नान पर्वों के दौरान 18,000 रुपये से 41,106 रुपये तक पहुंच गई हैं। चेन्नई से प्रयागराज की एकतरफा टिकट की कीमत हाल ही में 70,996 रुपये तक दर्ज की गई थी।
दिल्ली से प्रयागराज की हवाई यात्रा अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भी महंगी हो गई है। लंदन और बैंकॉक की एकतरफा फ्लाइट टिकट की तुलना में दिल्ली से प्रयागराज की टिकट ज़्यादा महंगी हो गई है। महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्वों जैसे मौनी अमावस्या (29 जनवरी), बसंत पंचमी (3 फरवरी), माघी पूर्णिमा (12 फरवरी) और महाशिवरात्रि (26 फरवरी) के दौरान हवाई किराए में अप्रत्याशित बढ़तरी दर्ज की गई है। उदाहरण के लिए, 31 जनवरी को दिल्ली से प्रयागराज की एकतरफा टिकट का किराया 33,590 रुपये था, जबकि 5,000 रुपये होता है। भुवनेश्वर से बैंकॉक कीमत से चार गुना अधिक कीमत उड़ान की कीमत 39,500 रुपये होती है। बैंकॉक की उड़ान की कीमत सामान्य दिनों में इस मार्ग के चार हजार तक से शुरू होती है। समाप्त होने के बाद की टिकट अकासा एयर की टिकट 4,500 रुपये, इंडिगो 4,059-9,888 में स्पाइसजेट 4,121-13,400 रुपये, अन्य एयरलाइंस 4,201-24,906 तो 5,639 में टिकट उपलब्ध होता है।

A large commercial airplane is shown from a rear perspective, flying low over an airport runway at sunset or sunrise. The sky is a warm orange and yellow, and the runway lights are visible below.